

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-765/2007

दानाराम

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), नागौर, राज.।
4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, लाडनू, जिला नागौर।
5. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, रिजनल ऑफिस, राजस्थान सरकार, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 31.07.2023

उपस्थित -

अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय गुप्ता, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2000 को हुई थी। सेवानिवृत्ति के पश्चात अपीलार्थी से इस आधार पर राशि वसूल की गई कि गलत रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई थी।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी से पूर्व में 26-ए का लाभ दिया गया जो कि नियमानुसार ही वेतन पद प्राप्त वेतन श्रृंखला में दुबारा पदोन्नति पर 26-ए का लाभ देय नहीं है।
3. हमारे द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।
4. इस प्रकरण में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति होने के पश्चात दिनांक 24.03.2007 (अनुलग्नक-6 व 7) के क्रम में 32411/- एवं 4060/- रुपये की राशि वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गए। यह प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी की स्वयं की गलती के कारण उन्हें गलत रूप से लाभ दिया गया है।
5. अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि उसकी सेवानिवृत्ति होने के पश्चात अपीलार्थी से 32411/- एवं 4060/- रुपये की वसुली की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है:-

State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

6. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए यह अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त प्रकार से अपीलार्थी से वसुल की गई राशि को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थी को लौटाई जाये। इस आदेश की पालना 3 माह में सुनिश्चित की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)